

दिनांक-18 दिसंबर 2024

7:20 AM

पहले मुख्य समाचार।

- प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट: लगभग 17 हजार 865 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट से प्रदेश के चौराहा विकास को मिलेगी गति।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा- प्रदेश सरकार नौजवानों के हित में पूरी प्रतिबद्धता से कर रही है कार्य।
- लोकसभा में एक राष्ट्र, एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक कल हुए पेश: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक को बताया देश हित में उठाया गया बड़ा कदम।
- वर्ष 2025 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए नहीं कराएगी भर्ती परीक्षाएं, केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर देगी विशेष ध्यान।
- बलिया को मिली नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात : मंत्रिपरिषद की बैठक में परिवहन विभाग को निशुल्क भूमि देने का हुआ निर्णय।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। लगभग 17 हजार 865 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790 करोड़ 49 लाख रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे पहले राज्य सरकार मानसून सत्र में 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7 लाख 66 हजार 513 करोड़ 36 लाख रुपए का हो गया है। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से बजट जारी किया जाएगा।

सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा विभाग में अब तक 1 लाख 60 हजार और पुलिस विभाग में 1 लाख 56 हजार पदों पर भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की बेहतरीन कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण प्रदेश में बड़ा निवेश आया है। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी आई है। बाइट(6)....

प्रदेश के अन्दर एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिये देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में माना चाहता है प्रदेश में निवेश करना चाहता है और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी उन इम्प्लाइमेंट रेट था वह 19 फीसदी से अधिक था और आज यह 2.4 है। ये चीजे दिखाती है सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। बाइट(7).....

2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी एक तिहाई रह गई थी। आज हम उसको दुगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अन्दर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है और मैं शीघ्र आप सबसे मिलना चाहूंगा हमें उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है।

अनुपूरक बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष ने इसे महज दिखावा बताया और कहा कि सरकार पहले मुख्य बजट के खर्च को सदन के पटल पर रखे। उधर, विधान परिषद में नेता सदन और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। वहीं विपक्ष ने शिक्षा के गिरते स्तर और रोजगार से युवाओं को वंचित किये जाने का मामला सदन में उठाया।

कल लोकसभा में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक पेश किया। विधेयक सदन में पेश किए जाने पर विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और मत विभाजन की मांग की। इसमें 269 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया। विपक्षी दलों ने विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। जिसके बाद श्री मेघवाल ने दोनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में पेश किए गए एक देश एक चुनाव बिल पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसे देश हित में उठाया गया कदम बताया।

जो विकास में पैसा लगाना चाहिये वह पैसा चुनाव बार-बार कराने में खर्च होता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि विजयनरी लीडर हैं उनके नेतृत्व में कई चीजें एक भारत-श्रेष्ठ भारत से लेकर के एक देश एक वोटर लिस्ट और एक चुनाव यह

दिशा में आज जो कदम बढ़ाया गया है उसके लिये बधाई भी देता हूं और देश के हित में यह फैसला है और यह बहुत बड़ा कदम है जो बहुत पहले होना चाहिये।

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज वाराणसी का दो दिवसीय दौरा करेंगी। राज्यपाल सुबह राजकीय विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से सड़क मार्ग द्वारा पिंडरा स्थित महारानी गुलाब कुंवारी महिला कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राज्यपाल महारानी बनारस महिला कॉलेज, रामनगर और महाराजा बलवंत सिंह डिग्री कॉलेज, गंगापुर की छात्राओं को डिग्री देने के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, शिवपुर में एचपीवी वैक्सिनेशन अभियान का शुभारंभ करेंगी। राज्यपाल रात्रि विश्राम काशी में ही करेंगी और कल सुबह सोनभद्र के लिए प्रस्थान करेंगी। राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2025 से, भर्ती परीक्षाओं के स्थान पर उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने पर विशेष ध्यान देगी। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सरकार दस नए पदों का सृजन कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। श्री प्रधान ने बताया कि पिछले दस साल में प्रति बच्चे पर किए जाने वाले खर्च में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चाइल्ड एक्सपेंडिचर की एक मोटा-मोटा लेखा जोखा आपके सामने मैं रखूं इसमें 130: की ग्रांथ हुई है, पिछले 10 साल में पहले 13-14 की बजट में इस अमाउंट का 10780 यह अभी 21-22 के बजट में 25043 रुपीज हुए हैं। ये 130: की ग्रांथ हो रही है।

प्रदेश सरकार ने बलिया जिले को नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात दी है। कल लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में बलिया के बैरिया में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना के लिए परिवहन विभाग को निशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अब बलिया में आईएसबीटी बन जाने से यहां से बिहार, बंगाल और दूसरे प्रदेशों के लिए बसों के संचालन में सुविधा होगी। उन्होंने कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को तीन हजार डीजल बसें खरीदने के लिए एक हजार करोड़ रुपए व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन मिलने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग की ओर से कल लखनऊ में तीन दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत हुई। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रभास कुमार ने बताया कि कार्यशाला में वॉटर बॉडीज की गणना के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आज लघु सिंचाई योजनाओं की सातवीं संगणना तथा जल निकायों की दूसरी संगणना के सम्बन्ध में तीन दिवसीय वर्कशॉप का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी लघु सिंचाई के योजनायें हैं जैसे डकवेल है, बोरवेल है या जो हमारे सरफेस वाटर बॉडीज है, जो रिसोर्सेज हैं उनकी सेंस किस प्रकार से की जाएगी। इस बार उसके सम्बन्ध में ये एक ट्रेनिंग मास्टर वर्कशॉप है। उसकी शुरुआत की गयी है।

केन्द्र सरकार भारत को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से सौ दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चला रही है। इसी क्रम में प्रदेश में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग के साथ ही उन्हें पर्याप्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य टीबी सेल के डॉ० शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान टीबी मरीजों को चिन्हित करने के साथ ही उन्हें जागरूक किया जायेगा। एक अभियान के तहत इन लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
